

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 319/2012/जोधपुर

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-द्वितीय,
जोधपुर

....अपीलार्थी

बनाम

प्लूटो इंटरनेशनल,
जोधपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित

.....अपीलार्थी की ओर से
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 53/आरवेट/जेयूडी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त द्वितीय, जोधपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2008-09 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 के तहत कायम की गई मांग राशि रुपये 59,150/- को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधि में द्वितीय तिमाही के बिक्री विवरण पत्र वेट-10 के साथ प्रस्तुत वेट-7 में मै. मोनार्क इम्पेक्स, जोधपुर टिन नं. 08142707018 के वेट इनवोइस नं. 31,32,33 दिनांक 22.07.08 रु. क्रमश 4,96,619/-, 4,86,760/- एवं 4,95,387/- का माल क्रय कर कुल 59,150/- रु. का इनपुट टैक्स क्लेम किया। कर निर्धारण अधिकारी ने जांच में पाया कि विक्रेता व्यवसायी मोनार्क इम्पेक्स, जोधपुर द्वारा कर की राशि जमा नहीं करवायी गई है जिससे व्यवसायी को राजस्थान वेट अधिनियम की धारा 18 एवं राजस्थान वेट नियम 2006 के नियम 18 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुए यह मानते हुए कि राजस्थान वेट अधिनियम की धारा 18 एवं राजस्थान वेट नियम 2006 के नियम 18 के अन्तर्गत वसूल किये गये कर को राजकोष में जमा कराने के पश्चात् ही क्रेता को आईटीसी स्वीकृत की जा सकती है, राशि रु. 59,150/- की आईटीसी अस्वीकृत करते हुए रिवर्स टैक्स व ब्याज आदेश दिनांक 31.01.2011 द्वारा आरोपित किया गया।

2/12

लगातार.....2

व्यवसायी द्वारा इस आदेश के विरुद्ध उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील आधार में कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा क्लेम आईटीसी में से फर्म मै. मोनार्क इम्पेक्स, जोधपुर से प्राप्त माल के बिलों पर आगत कर राशि को गलत एवं अविधिक आधार पर अस्वीकार कर ब्याज का आरोपण भी कर दिया गया है। उन्होंने कथन किया है कि विवादित फर्म मै. मोनार्क इम्पेक्स, जोधपुर निर्धारण प्राधिकारी के वृत्त में पंजीकृत है इस फर्म का कर निर्धारण भी कर दिया गया है तथा विवादित करदयेता को सम्मिलित करते हुए मै. मोनार्क इम्पेक्स, जोधपुर के विरुद्ध मांग भी सृजित की गयी है। मै. मोनार्क इम्पेक्स, जोधपुर ने अपने लेखों एवं वेट 08 में अपीलार्थी को की गयी बिक्री को भी पूर्ण रूप से दर्शाया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का आईटीसी का मुजरा नहीं दिया जाना पूर्णतया अविधिक है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय कर बोर्ड का निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त 'ए' श्रंगंगानगर बनाम मै. विजय ट्रेडर्स, श्रीगंगानगर के निर्णय की प्रति पेश की जिसमें यह अवधारित किया गया है कि क्रय कर्ता व्यवसायी द्वारा वास्तविक खरीद पर ली जाने वाली आईटीसी को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि विक्रेता व्यवसायी द्वारा अपना कर जमा कराने के संबंध में दायित्व पूर्ण नहीं किया गया एवं यह भी अवधारित किया कि कर का दायित्व प्रथम बिन्दू पर ही रहेगा जब तक कि इसे अन्यथा रूप से प्रमाणित न कर दिया जावे। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण भी प्राप्त नहीं किया कि यह खरीद वास्तविक न होकर बोगस है बल्कि मै. मोनार्क इम्पेक्स, जोधपुर के कर निर्धारण से यह प्रमाणित है कि संव्यवहार सही एवं वास्तविक है। अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 24.08.2011 द्वारा माननीय कर बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त 'ए' श्रंगंगानगर बनाम मै. विजय ट्रेडर्स, श्रीगंगानगर (27 टैक्स अपडेट पेज 109) के प्रकाश में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश निरस्त किया जिसके विरुद्ध राजस्व की ओर से यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज की जाकर रिकार्ड व प्रत्यर्थी को तलब किया गया। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें।
4. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अनुचित बताते हुये राज्य पक्ष की अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
5. हमने पत्रावाली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
6. आलौच्य अवधि में जिस विक्रेता व्यवहारी से क्रय किये गये माल की राशि पर देय वेट का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, जांच में यह पाया गया कि यह

राशि राजकोष में जमा नहीं हुई हैं। वेट अधिनियम की धारा 18(2) के तहत आई.टी.सी. का क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि इस पेटे देय कर राजकोष में जमा हो चुका हो एवं यह प्रमाणित करने का दायित्व व्यवहारी का है कि देय कर राजकोष में जमा हो चुका है। प्रत्यर्थी व्यवहारी खरीदे गये माल पर कर चुकाये जाने के सबूत के भार का निर्वहन करने में असफल रहा है।

7. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि क्या किसी क्रेता व्यवहारी की खरीद पर क्लेम की गई आई.टी.सी. के दावे को विक्रेता व्यवहारी द्वारा बिक्री पर कर जमा नहीं कराये जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार किया जाने योग्य है अथवा अस्वीकार किये जाने योग्य है ?

8. आई.टी.सी. क्लेम के संबंध में धारा 10 जो निम्न प्रकार है :-

धारा 10. Burden of proof. -

The burden of proving that any sale or purchase effected by any person is not liable to tax for any reason under this Act or to prove for entitlement of input tax credit on any purchases, shall be on such person.

के विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए क्रय-विक्रय को प्रमाणित करने का दायित्व संबंधित पक्षकार का है।

9. Input Tax Credit क्लेम करने के संबंध में अधिनियम की धारा 18 (2),(3) निम्न प्रकार है :-

18. Input Tax Credit. -

(1)

(2) **The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed. (This amended provision has been substituted in section 18(2) of the original Act vide The Rajasthan Value Added Tax (Amendment Bill 2009) Bill no. 8 of 2009 which has given retrospective effect from 01-04-06)**

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases -

(i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or

(ii) of goods made in the course of import from outside the State; or

(iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or

(iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or

(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.

10. उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं तथ्यों से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी को आई.टी.सी. क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि इस पेटे देय कर राजकोष में जमा हो चुका हो। विक्रेता फर्म द्वारा टैक्स जमा नहीं करवाया गया है जिससे इसके पेटे इनपुट टैक्स दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः व्यवहारी धारा 18(2) व (3) के तहत आई.टी.सी. क्लेम का अधिकारी नहीं रहता है।

11. इसी प्रकार Non-Obstante Clause के सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फुल बैंच के निर्णय (2006) 148 एस.टी.सी. 356 भदौरिया ग्राम सेवा संस्थान बनाम सहायक आयुक्त, सेल्स टैक्स, इलाहाबाद व अन्य में निम्न मत प्रतिपादित किया गया है :-

"Having given our anxious considerations to the various submissions made by the learned counsel for the parties, we find that Section 7-D which provides for composition of tax liability, starts with a **non-obstante clause**. A plain reading of Section 7-D of the Act shows that an option has been given to a dealer who is covered by a scheme issued by the State Government from time to time to opt for payment of lump sum amount in lieu of the amount of tax. It excludes the applicability of other provisions of the Act which deals with the assessment and payment of tax. A **non-obstante clause**, as observed by the Apex Court in the case of State of Bihar v. Bihar M.S.K.K. Mahasangh and others, AIR 2005 SC 1605, is generally appended to a section with a view to give the enacting part of the section, in case of a conflict, an overriding effect over the provision in the same or other Act mentioned in the non-obstante clause. It is equivalent to

२५

saying that in spite of the provisions or Act mentioned in the non-obstante clause, the provision following it will have its full operation or the provisions embraced in the non-obstante clause will not be an impediment for the operation of the enactment or the provision in which the non-obstante clause occurs.

12. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पंजीयन प्रमाण-पत्र के सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त (1965) 16 एस.टी.सी. 271 (उड़ीसा) नौरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा में निम्न निर्णय पारित किया गया है :-

"Even as regards proprietary interest it was held as early as 1899 in *Prosunno Coomar Roy v. The Secretary of State for India in Council*, that any conduct of a Government servant in violation of his duty, will not operate as estoppels against Government. This principle has been followed in *Secretary of State for India v. Faredoon Jijibhai Divecha* 5, where it was held that the mistaken interpretation of a grant by officers of Government and the consequent mistaken acts would not operate as estoppels as against the Crown. Here, it has been found as a fact that persons who had no business at all succeeded in obtaining certificates of registration from the Sales Tax Authorities either due to the negligence or with the connivance of the Sales Tax Authorities and hence the grant of certificates of registration to them should be held to have been made by mistake. The Sales Tax Authorities had no jurisdiction to grant such certificates to fictitious persons or to persons who had no business. Hence though these persons may technically be said to be holders of registration certificates, nevertheless, in the eye of law, they cannot be held to be registered dealers because they have not been "validly" registered under the provisions of the Act and any mistake committed by the subordinate officers of the Sales Tax Department either due to negligence or due to collusion, cannot, on general principles, operate as estoppels against Government.

13. इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2013) 66 वी.एस.टी. 75 यू.एस.ए. एजेंसीज व अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी अत्तुर (ग्रामीण) में निम्न निष्कर्ष दिया है :-

"After extracting the quote from "Maxwell on The Interpretation of Statutes", 10th Edition at page 381 and observing that it is for the Court to ascertain the real intention of the Legislature by carefully examining the scope of Statute, in AIR 1961 SC 751 [*State of U.P. and others v. Babu Ram Upadhy*], the Hon'ble Supreme Court held as under:-

२४/

"29. The relevant rules of interpretation may be briefly stated thus: When a statute uses the word 'shall', prima facie, it is mandatory, but the Court may ascertain the real intention of the legislature by carefully attending to the whole scope of the statute. For ascertaining the real intention of the Legislature the Court may consider, inter alia, the nature and the design of the statute, and the consequences which would follow from construing it the one way or the other, the impact of other provisions whereby the necessity of complying with the provisions in question is avoided, the circumstance, namely, that the statute provides for a contingency of the non-compliance with the provisions, the fact that the non-compliance with the provisions is or is not visited by some penalty, the serious or trivial consequences that flow therefrom, and, above all, whether the object of the legislation will be defeated or furthered."

14. इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का अधिकार निहित अधिकार या अलोप्य अधिकार नहीं है, लेकिन अधिनियम के अधीन एक प्रदत्त लाभ है जो विशेष संभाव्यता या विशेष शर्तों के अधीन प्रदत्त किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का अधिकार पंजीकृत व्यवहारियों को निरपेक्ष प्रदत्त व अलोप्य अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

15. यह (इनपुट टैक्स क्रेडिट) वास्तव में एक लाभ या अनुग्रह है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रियायती प्रावधानों का अर्थ बहुत कठोरता से लगाया जाना चाहिये। विधि का सुस्थापित नियम है कि कोई व्यक्ति जो मुक्ति या रियायती दर का दावा करता है, के द्वारा आज्ञापक विधिक अपेक्षाएँ यथावत पूर्ति की जानी चाहिये। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ का प्रयोग करने की रियायती अन्ततोगत्वा उपभोक्ता पर Cascading effect of tax burden में कमी के लिये दिया गया है। मूल्य परिवर्धित कर ढांचे का उद्देश्य प्रक्रिया का सरलीकरण करके तथा अधिक पारदर्शी व्यवस्था करते हुए राजस्व में वृद्धि करने का रहा है।

16. इस सन्दर्भ में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 65 वी.एस.टी.सी. 260 जायम एण्ड कम्पनी बनाम सहायक आयुक्त (सी.टी.) में पैरा 20 में वेट लागू करने की अवधारणा का उल्लेख निम्न प्रकार है :-

".....The White Paper circulated by the Empowered Committee of State Finance Ministers furnished the following rationale for the introduction of VAT:

"In the existing sales tax structure, there are problems of double taxation of commodities and multiplicity of taxes, resulting in a **cascading tax burden**. For instance, in the existing structure, before a commodity is produced, inputs are first

taxed, and then after the commodity is produced with input-tax load, output is taxed again. This causes an unfair double taxation with cascading effects. In the VAT, a set-off is given for input tax as well as tax paid on previous purchases. In the prevailing sales tax structure, there is in several States also a multiplicity of taxes, such as turnover tax, surcharge on sales tax, additional surcharge, etc. With introduction of VAT, these other taxes will be abolished. In addition, Central sales tax is also going to be phased out. As a result, overall tax burden will be rationalised, and prices in general will also fall. **Moreover, VAT will replace the existing system of inspection by a system of built-in self-assessment by the dealers and auditing. The tax structure will become simple and more transparent. That will improve tax compliance and also augment revenue growth. Thus, to repeat, with the introduction of VAT, benefits will be as follows:**

- û a set-off will be given for input tax as well as tax paid on previous purchases
- û other taxes, such as turnover tax, surcharge, additional surcharge, etc., will be abolished.
- û overall tax burden will be rationalised.
- û prices will be self-assessment by dealers
- û transparency will increase
- û there will be higher revenue growth"

In order to examine the controversy raised in these writ petitions and to test the validity of the impugned provision, a birds eye view of the design of the VAT Act, its concept, coverage, the compulsory requirement to be complied with and other relevant details has to be looked into."

".....Therefore, the net effect of the VAT system is to rationalise the tax burden and bring down in general the price level, stop the tax rate war, and with a view to bring in **simplicity and transparency in the tax structure thereby improving the tax compliance and eventually to ensure growth the revenue. The above in broad terms is the concept of VAT."**

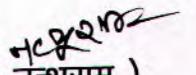
" "Input tax credit", which is in the nature of the concession or indulgence, could be availed only in the manner prescribed under Section 19. The law is well settled that the person, who claims exemption or concessional rate, must obey and fulfil the mandatory requirements exactly. Unless there is strict compliance with the provisions of the statute, the registered dealer is not entitled to claim input tax credit.

17. उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि विक्रेता ने कर जमा नहीं कराया है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी. सी. का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स व ब्याज अपास्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

217

18. फलतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2011 निरस्त किया जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.2011 की पुष्टि की जाती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रकरण के न्यायिक प्रक्रियाधीन रहने की अवधि में इस दौरान यदि विक्रेता व्यवहारी मै. मोनार्क इम्पेक्स, जोधपुर जिससे क्रय किये गये माल पर क्रेता व्यवहारी ने इनपुट टैक्स क्लेम किया है, द्वारा यदि यह इनपुट टैक्स राजकीय कोष में जमा करवा दिया गया है या विभाग ने कर निर्धारण के समय विक्रेता व्यवहारी मै. मोनार्क इम्पेक्स, जोधपुर के विरुद्ध कायम की गई मांग वसूल कर ली है तो क्रेता व्यवहारी द्वारा क्लेम किए गए इनपुट टैक्स के संबंधित कर निर्धारण अधिकारी नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है।

19. निर्णय सुनाया गया।


(नन्धूराम)
सदस्य